भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2276

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना

†2276. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में ओडिशा के कंधमाल और बौध जिलों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं-जैसे आपातकालीन देखभाल, विशेषज्ञ की उपलब्धता, निदान, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और पैलियेटिव देखभाल (विशेष रूप से कैंसर स्क्रीनिंग) में कमियों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने इन अल्पसेवित जिलों में नई अभिघात देखभाल इकाइयाँ, सीएसएसडी सुविधाएँ, उन्नत निदान केंद्र और क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और यदि हों, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एवीएचआईएम), आपातकालीन देखभाल सुदृढीकरण योजना या अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना कार्यक्रमों के अंतर्गत इन परियोजनाओं के अनुमोदन और स्वीकृत करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कंधमाल जिले के फुलबानी में एम्स, भुवनेश्वर का उप-केंद्र स्थापित करने का विचार है ताकि सुदूर एवं जनजातीय आबादी हेतु तृतीयक देखभाल, विशेषज्ञ आउटरीच, दूरस्थ चिकित्सा और निदान को सुदृढ़ किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीपीआई) के रूप में मिले प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रस्ताव को रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (RoPs) के रूप में वित्तीय मंजूरी देती है। एनएचएम के अंतर्गत प्रस्ताव पीआईपी के रूप में प्राप्त होते हैं और उनके लिए स्वीकृतियां नीचे दिए गए लिंक के अनुसार उपलब्ध हैं:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

एनपीसीसी बैठकों के दौरान, राज्यों से जुड़े मुख्य डिलिवरेबल्स को पहले से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में मापा जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के तहत एक मुक्त रूप से संशाधित टूलकिट और एक डैशबोर्ड शुरू किया है। आईपीएचएस डैशबोर्ड एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के आईपीएचएस 2022 मानकों के पालन हेतु निगरानी करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ये टूल राज्यों को उनकी कमियों की पहचान करने और आवश्यक मानकों को हासिल करने के लिए लक्षित सहायता प्राप्त करने में मदद करते हैं।

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और नीति आयोग के अधिदेशानुसार प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों की व्यवस्थित रूप से समीक्षा और निगरानी करता है।

इस स्कीम के तहत प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) का आयोजन भी किया जाता है । सीआरएम की मुख्य कार्यनीतियाँ और प्राथमिकता स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, प्रमुख संकेतकों की प्रगति में रुझानों की पहचान करना, नई पहलों को लागू करने के लिए राज्य की तैयारी का मूल्यांकन करना और विभिन्न भागीदारों के साथ प्रगति के संबंध में चुनौतियों का विश्लेषण करना और समन्वय तंत्र की समीक्षा करना है।

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम5-एबीएचआईएम) केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके कार्यान्वयन की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है। इस योजना के तहत, ओडिशा राज्य के लिए 28 सघन चिकित्सा ब्लॉक (50 बेड वाले: 27 और 100 बेड वाले: 1) और 30 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

पन्द्रहवें वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान के तहत **,** योजना अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 24,503.49 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से ओडिशा के लिए कुल 2,450.39 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की गई है। मंज़ूर किए गए कार्यों में भवन रहित 966 उप स्वास्थ्य केंद्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम), 396 भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र –एएएम (पीएचसी-एएएम), 117 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू), और 140 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) का निर्माण शामिल है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): इस योजना का उद्देश्य किफायती तृतीय स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और पूरे देश में अच्छी मेडिकल शिक्षा के लिए सुविधाओं को मज़बूत करना है। ओडिशा में, पीएमएसएसवाई के तहत तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है, जिनके नाम हैं एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बेरहामपुर, वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुरला, और सरकारी मेडिकल कॉलेज, कटक इन सभी को सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाने की मंज़ूरी मिल गई है।

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंज़ूरी दी गई है। ओडिशा में, बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी, जाजपुर और कालाहांडी में सात नए मेडिकल कॉलेजों को मंज़ूरी दी गई है।

(घ): कंधमाल जिले के फूलबनी में एम्स भुवनेश्वर का सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****